

# The Gazette of India

# असाधार**गा** EXTRAORDINARY

भाग II—कण्ड 3—जप-कण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

й. 136] No. 136] नई विल्ली, सोमवार, मार्च 30, 1987/धैन्न 9, 1909

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 30, 1987/CHAITRA 9, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संस्था की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

### उद्योग मंत्रालय

(बौद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1987

### ग्रावेश

का. या. 266(प्र) :— 18कक/पार्ड. डी. प्रार. ए. /87: — मारत सरकार के उद्योग मंतालय (प्रीचीगिक विकास विमाग) के आदेश सं. का. था. 320(प्र)/18कक/प्रार्ड. डी. प्रार. ए. /79 तारीख 26 मर्ड, 1979 द्वारा (जिसे इसमें इसके पण्चात् उकत भादेश कहा गया है) मैससं अपीलो जिप्पर कम्पनी प्रार्डवेट लिमिटेड, कलकता नामक सम्पूर्ण प्रौचीगिक उपक्रम का प्रवंध उद्योग (विकास और विनियमन) प्रधितियम, 1951 (1951 का 65) की थारा 18कक की उपश्रारा (1) के व्यप्त (क) के प्रधीन 25 मर्ड, 1982 तक की, जिसमें यह तारीव्य भी सम्मिलत है, तीन वर्ष की अपित के लिये प्रश्म किया गया था और सम्मिलत है, तीन वर्ष की अपित के लिये प्रश्म किया गया था और का, जिसे प्रवं सचिव भीवीगिक पुतर्तिमींग विभाग, परिवयी बंगान सरकार का, जिसे प्रवं सचिव भीवीगिक पुतर्तिमींग विभाग, परिवयी बंगान सरकार कहा जाता है, उक्त व्योगिक उपक्रम का प्रवंध प्रहण करते के लिये प्राधिकृत किया गया था ;

घौर, केन्द्रीय सरकार ने प्रभाग यह राव हो गर कि लोकित्ति में यह समीजीन है कि उक्त प्रादेश पूर्वोक्त तीन वर्ष की प्रविध की समाप्ति के पश्चान् प्रभावी बना रहे, 31 मार्च, 1987 मक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मितिन है, भीर प्रविध के लिये ऐसे जारी रहने के लिये, समय-ममय पर निवेश जारी किये थे। (देखिए भारत सरकार के उद्योग मंजालय (घौछोगिक विकास विभाग) के प्रादेश सं.का. प्रा. 246(प्र)/18कक/प्राई.डी. प्रार.ए./82 तारीख 25 मई, 1982, सं. का. प्रा. 832(प्र)/18कक/प्राई.डी. प्रार.ए./82 तारीख 24 नवस्वर, 1982, सं. का. प्रा. 838(प्र)/18कक/प्राई.डी. प्रार.ए./83, तारीख 31 मई, 1983, सं. का. प्रा. 872(प्र)/18कक/प्राई.डी. प्रार.ए./83 तारीख 30 नवस्वर, 1983, मं. का. प्रा. 472(प्र)/18कक/प्राई.डी. प्रार.ए./84 तारीख 28 जून, 1984, मं. का. प्रा. व 975(प्र)/18ककमाई.डी. प्रार.ए./84 तारीख 29 दिसम्बर, 1984, का. प्रा. 275(प्र)/18कक/प्राई.डी. प्रार.ए./85 तारीख 29 मार्च, 1985 एवं का. प्रा. 146(प्र)/18कक/प्राई.डी. प्रार.ए./86 तारीख 39 मार्च, 1986);

श्रीर केन्द्रीय गरतार का पर्धिय है कि अक्टिन में पर्मनी बोत है कि उक्त आदेण 31 मार्च, 1938 तह की, दिनमें प्रतामिश्र ना सम्मिलत है, और अपि के निये स्मारों बाग रहे; प्रतः श्रम, केन्द्रीय सरकार उचीन (विकास श्रीर विनियमत) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की आरा 18क की उपयास (2) की परन्तुक के साथ पिठत आरा 18क की उपधास (2) द्वारा प्रदश्च शिक्तियों का प्रयाग करते हुए यह निवेश देती है कि उक्त आदेश 31 मार्च, 1988 नक्ष की, जिसमें यह तारीक भी सम्मितित है, और श्रमधि के लिये प्रभावीं बना रहेगा।

[फा.सं. 2(23)/80-ती.यू.एस.] ए.बी. गोकव, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 30th March, 1987

### **ORDER**

S.O. 266(E)|18AA|IIIRA|87.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) 320(E)|18AA|1DRA|79, dated the 26th No. S.O. May, 1979 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the whole of the Industrial Undertaking known as Messrs Apollo Zipper Company Private Limited, Calcutta was taken over under clause (a) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of three years upto and inclusive of the 25th May 1982 and the Secretary, closed the Sick Industries Department, Government of West Bengal called Secretary, Industrial Reconstruction Department, Government of West Bengal, was authorised to take over the management of the said Industrial Undertaking;

And whereas, the Central Government being of opinion that it is expedient in the Public interest that the said Order should continue to have affect after the expiry of the period of three years aforesaid, had issued directions from time to time, for such continuance for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1987 (vide Orders of the Govt. of India in the Ministry of Industry, Department of Industrial Development) Nos. S.O. 246(E)|18AA| Industrial Development) Nos. S.O. 246(E)|18AA| IDRA|82, dated the 25th May, 1982, S.O. 832(E)| 18AA|IDRA|82, dated the 24th November 1982, S.O. 385(E)|18AA|IDRA|83, dated the 31st May, 1983, S.O. 872(E) | 18AA | IDRA | 83, dated the 30th November, 1983, S.O. 472(E)|18AA|IDRA|84, dated the 28th June 1984, S.O. 975(E) | 18AA | IDRA | 84, dated the 29th December, 1984, S.O. 275(E) 18AA IDRA 85, dated the 29th March, 1985 and S.O. 146(E) | 18AA | IDRA | 86 dated the 31st 1986;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect for a period upto and inclusive of the 31st March 1988.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA, read with proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulations) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st March 1988.

[File No. 2(23) 80 CUS] A. V. GOKAK, Jt. Secy.